

पीएम से मिले स्टालिन

● मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किन मुद्दों पर हुई बात?

नयी दिल्ली, (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसी दौरान एमके स्टालिन ने राज्य में महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए शीघ्र धन जारी करने पर मांग की। डीएमके सूत्रों ने खुलासा किया कि स्टालिन का लक्ष्य चेन्नई मेट्रो और सार्वभौमिक शिक्षा कार्यक्रमों जैसी पहल के लिए वित्तीय सहायता सुरक्षित करना था।

स्टालिन की यात्रा इन फंडों के आवंटन में देरी पर चिंताओं के बीच हो रही है, तमिलनाडु सरकार कथित तौर पर पीएम-एसएचआरआई स्कूलों की योजना को एसएसए फंड जारी करने से जोड़ने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव से नाखुश है। गुरुवार शाम राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने पर स्टालिन का सांसद टीआर बालू, तिरुचि शिवा, दयानिधि मारन, के कनिमोझी और



टी सुमति सहित द्रमुक नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रीय राजधानी में अपने आगमन के तुरंत बाद, स्टालिन ने कानूनी टीम से मुलाकात की, जिसने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री संधिल बालाजी के मामले को संभाला था, जिन्हें गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। मुख्यमंत्री ने संधिल बालाजी की दयानिधि मारन, के कनिमोझी और

योगी सरकार का दावा पीड़ित एससी-एसटी परिवारों की मदद के लिए 1400 करोड़ से ज्यादा आवंटित किए

लखनऊ, (एजेंसी)। योगी सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में पीड़ित एससी-एसटी परिवारों की मदद के लिए योगी सरकार ने 1400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की है। प्रदेश में एससी-एसटी पीड़ितों को 85,000 रुपये से लेकर 8.25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की पीड़िताओं को साढ़े सात वर्ष में 1447 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। यह सहायता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989) और नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम के तहत प्रदान की जाती है। अपराध की गंभीरता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा



सके कि पीड़ितों और उनके परिवारों को जरूरत पर सरकार की तरफ से मदद मिले। केंद्र सरकार के

आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है प्रदेश सरकार समाज कल्याण विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य पीड़ितों और उनके परिवारों को समय पर आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उन्हें सहायता मिल सके। इस पहल के तहत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि परिवारों को जांच और परीक्षण के महत्वपूर्ण बिंदुओं के आघार पर आवश्यक सहायता मिले। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी व तहसील स्तर पर एसडीएम की अद्यक्षता में गठित है समिति विभिन्न अपराधों से पीड़ित एससी-एसटी की महिलाओं को न्याय मिले। इसके लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सतर्कता व मॉनीटरिंग समिति कार्य करती है,

जबकि तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की व्यवस्था की गई है। अपराध की प्रकृति के आधार पर निर्धारित की जाती है सहायता हत्या या अत्याचार के कारण मृत्यु होने पर परिजनों को 8.25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। इसमें मुआवजा दो चरणों में वितरित किया जाता है। 50 प्रतिशत राशि पोस्टमार्टम के तुरंत बाद और शेष 50 प्रतिशत औपचारिक रूप से अदालत में चार्जशीट जमा होने के बाद प्रदान की जाती है। बलात्कार या सामूहिक बलात्कार (धारा 375, भारतीय दंड संहिता) के मामले में, पीड़ित 5.25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के हकदार हैं। कानूनी प्रक्रिया के दौरान यह सहायता चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जाती है।

रॉबर्ट वाड्रा का मोदी पर पलटवार, बोले- अगर मैं गलत हूं तो साबित करो

नयी दिल्ली, (एजेंसी)। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर तंज कसा है। इसके जवाब में रॉबर्ट वाड्रा ने पीएम मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा, ध्याप साबित करें कि मेरी कोई जमीन हरियाणा में है या मैंने... हरियाणा डेस्क, हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर तंज कसा है। इसके जवाब में रॉबर्ट वाड्रा ने पीएम मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा, ध्याप साबित करें कि मेरी कोई जमीन हरियाणा में है या मैंने कोई गलत काम किया है। आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। वाड्रा ने कहा कि प्रान्तमंत्री अपने भाषणों में लगातार उनका नाम लेते हैं। उन्होंने बताया कि मोदी की सरकार को दस साल हो गए हैं और सभी एजेंसियों ने जांच की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। वाड्रा ने चेतावनी दी कि अगर कुछ है तो उसे साबित करें। कोई सबूत नहीं वाड्रा ने यह भी कहा कि मोदी पिछले दस सालों से उन्हें फर्जी मुद्दों में उलझाए हुए हैं। हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार ने खुद अदालत में लिखित में कहा था कि वाड्रा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वाड्रा ने पीएम मोदी से सवाल किया कि वे किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस तरह वाड्रा ने स्पष्ट किया कि उन्हें राजनीतिक बदले की भावना से निशाना बनाया जा रहा है।

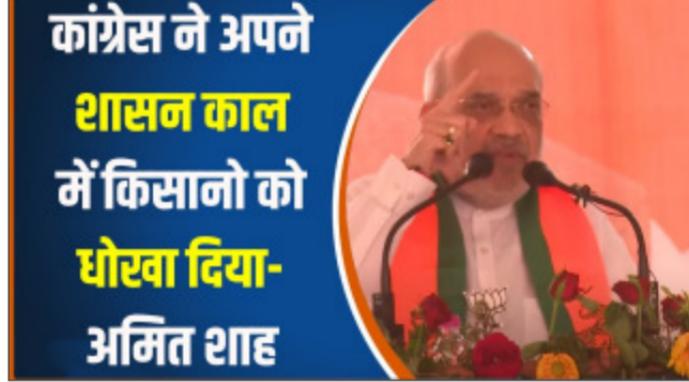


रॉबर्ट वाड्रा का मोदी पर पलटवार, बोले- अगर मैं गलत हूं तो साबित करो

‘किसानों से झूठ बोलना बंद करे कांग्रेस’

- अमित शाह का राहुल से सवाल, खरीफ और रबी की फसल कौन सी है?
- जिले के लिए किए वादे, कांग्रेस पर साधा निशाना, बागियों को वोट न देने की अपील

हरियाणा, (एजेंसी)। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में ताकत झोंक रखी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रेवाड़ी में पहुंचे। हरियाणा के रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। शाह ने अपना संबोधन भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ शुरू किया। मंच पर उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, सुखेंद्र नागर सहित स्थानीय नेता मौजूद रहे। अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के वायदे जनसभा में बताए और साथ में जिले के लिए भी कई वादे किए। उन्होंने बागियों को वोट न देकर केवल भाजपा कैंडिडेट को ही वोट देने की बात कही। अमित शाह ने रेवाड़ी से प्रत्याशी लक्ष्मण यादव, बावल से



डॉक्टर कृष्ण कुमार व कोसली से अनिल यादव के लिए वोट की अपील की। मौती चौक घंटेघर मंदिर को भी मंत्री शाह ने प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने राव तुलाराम को याद करके प्रणाम किया। अमित शाह ने कहा कि आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। शाह ने अपना संबोधन और गीता की भूमि, ये हरियाणा की भूमि शक्ति और समृद्धि की भूमि है। हमारे गुजरात में हरियाणा पंजाब को सम्मान से देखा जाता है। हरियाणा की भूमि ने हर दसवां जवान सेना में भेजा है। पीएम मोदी ने यहीं से की थी चुनाव प्रचार की शुरुआत अमित शाह ने कहा कि साध में जिले के लिए भी कई वादे किए। उन्होंने बागियों को वोट न देकर केवल भाजपा कैंडिडेट को ही वोट देने की बात कही। अमित शाह ने रेवाड़ी से प्रत्याशी लक्ष्मण यादव, बावल से सम्मान न करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा का एक भी अग्नीवीर पेंशन वाली नौकरी से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार हर अग्नीवीर को पक्की नौकरी देगी। भाजपा की सरकार आई, पूरे हरियाणा की सरकार आई अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में एक जिले का मुख्यमंत्री आता था तो एक जिले का विकास होता था। अग्नीवीर बढ़ता था। दूसरे जिले का आता था दूसरे का काम होता था। गुंडागर्दी बढ़ती थी। भाजपा सरकार आई पूरे हरियाणा की 36 बिरादरी

राहुल गांधी अज्ञानी, विदेशों में देश का कर रहे अपमान: डॉ. मोहन यादव

चरखी दादरी (हरियाणा), (एजेंसी)। दादरी हलके से भाजपा प्रत्याशी की ओर से आयोजित जनसभा में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किए। हरियाणा सरकार की उपलब्धियों के कसीदे पढ़े। हरियाणा के चरखी दादरी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने



दादरी हलके में आयोजित भाजपा प्रत्याशी की जनसभा में राहुल गांधी पर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अज्ञानी हैं। वह विदेशों में जाकर देश का अपमान करते हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में देश का मान-सम्मान बढ़ा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी सुनील सांगवान के समर्थन में मिसरी गांव में मतदान की अपील करने पहुंचे डॉ. यादव ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर पाकिस्तान के हितां की बात करते हैं। वह हरियाणा आए जरूर हैं, लेकिन नासमझ हैं, नादान हैं। कहा कि देश के खिलाफ जाने वालों को चुनाव में वोट की वोट से जनता सबक सिखाएगी। कहा कि भाजपा ने हरियाणा में खूब विकास कार्य करवाए हैं। जनहित की योजनाएं लागू की हैं। जनसभा में भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह व पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान भी मौजूद रहे।

जम्मू-कश्मीर के युवाओं ने आतंकवाद को नकारा: जेपी नड्डा



जम्मू, (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में अतिम चरण के चुनाव को लेकर भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा रही है। आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू में प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर चुनाव के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि यह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें बूथ-कैप्चरिंग, गोलीबारी या आतंकवादी हमलों का कोई निशान नहीं था। उन्होंने कहा कि चुनाव देखने के लिए दुनिया भर के 16 देशों के राजदूत यहां आए थे। यह एक ऐतिहासिक क्षण है

● जेपी नड्डा बोले- बुलेट के बजाय बैलेट का रास्ता चुना

उन्होंने कहा कि आपको जानकर खुशी होगी कि 16 देशों के एंबेसडर यहां का चुनाव देखने आए थे और उन्होंने देखा कि कैसे यहां की कानून व्यवस्था पर नियंत्रण और प्रजातंत्र में लोगों ने बड़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया। इसके साथ ही नड्डा ने कहा कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक इवेंट है, जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट को नकार कर बुलेट का रास्ता चुना है। उन्होंने कहा कि जम्मू असतन साल में 100 दिन बंद रहता था, पिछले पांच साल में जम्मू न बंद हुआ और न ही कोई हड़ताल हुई। जम्मू-कश्मीर के युवाओं ने आतंकवाद को नकार दिया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। अनुच्छेद-370 के समाप्त होने से पहले यहां लगभग 300-400 आतंकवादी पैदा होते थे।

● राहुल गांधी ने युवा और किसानों के जरिए हर वर्ग को साधा, 29 मिनट चला भाषण

बरवाला, (हरियाणा), (एजेंसी)। 29 मिनट के भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी, अदानी और अंबानी पर सबसे अधिक हमले किए। करनाल के बच्चे देव का जिक्र कर लोगों को भावनात्मक तौर पर जोड़ने का प्रयास किया। हरियाणा के हिसार के बरवाला में हरियाणा में चुनाव प्रचार के पहले दिन बरवाला पहुंचे राहुल गांधी ने अपना भाषण हरियाणा के युवाओं, किसानों, अंबानी-अदानी और पीएम नरेंद्र मोदी पर केंद्रित रखा। उन्होंने बेरोजगारी का समापन संविधान पर खतरा बता व अग्निवीर के मुद्दे पर युवाओं को साधा, वहीं एमएसपी के जरिए किसानों को जोड़ने का प्रयास किया। युवाओं के परिवारों के दर्द को करनाल के एक बच्चे देव के माध्यम से बताकर लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा। अग्निवीर के मुद्दे को उठाते हुए सैनिकों की पेंशन खत्म



करने को भी अंबानी से जोड़ा। राहुल गांधी ने 29 मिनट के भाषण में यह बताने का प्रयास किया कि युवाओं की बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा और तीन कानूनों के पीछे मोदी के जरिए अंबानी थे। उन्होंने अपने भाषण का समापन संविधान पर खतरा बता कर किया। बरवाला की कपास मंडी में आयोजित विजय संकल्प रैली में संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में सभी की सरकार बनेगी। छत्तीस बिरादरी को एक साथ मिलकर सरकार बनानी है। दरअसल वह कांग्रेस के प्रति भाजपा की ओर से बनाए जा रहे

सरकार घबराई हुई है, प्रधानमंत्री परेशान हैं, ज्यादा नहीं बोलते: जयराम रमेश

नयी दिल्ली, (एजेंसी)। अपना हमला जारी रखते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम और श्वघोषित चणक्य ने सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। वे आरक्षण पर 50: की सीमा हटाएंगे या नहीं इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश लगातार मोदी पर हमलावर रहते हैं। इसी बीच एक बार फिर से जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान के बहाने रमेश ने कहा कि भाजपा ने चुनाव के दौरान 3400 पारश और संविधान बदलने की बात की। हमारे गैर-जैविक पीएम चुप रहते हैं और दूसरों से बयान दिलवाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तीन काले कानूनों को वापस लाने की मांग बीजेपी की ओर से हर दिन आती है। अपना हमला जारी रखते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम और श्वघोषित चणक्य ने सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। वे आरक्षण पर 50: की सीमा हटाएंगे या नहीं इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के राज्य चुनावों में ये बड़े मुद्दे बनने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 4 जून, 2024, भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था... आगामी राज्य चुनावों के बाद आप और अधिक बदलाव देखेंगे। यह पूछने पर कि हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव किस तरह के बदलाव लाएंगे, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम का चेहरा देखिए। वह परेशान है। वह ज्यादा नहीं बोलते। वह दुनिया के देशों का दौरा करते हैं।



नीति का विरोध

आक्रमण के कारक अमन कराने में उतनी चुस्ती-फुर्ती से कारगर नहीं होते। इससे युद्ध लंबे-लंबे और भयावह होते गए हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के ही डेढ़ साल हो गए हैं तो सात महीनों से फिलिस्तीन और इज़्राइल के बीच घमासान जारी है। दोनों मामलों में विराम कोशों दूर है। फिलिस्तीन से इज़्राइल की पिछले महीने युद्ध विराम वार्ता सह समझौते की तारीख रद्द हो गई थी। अब इसी हफ्ते का नया दिन मुकर्रर हुआ है। यह राहत की बात है। अमेरिका की निगहबानी में मिश्र और कतर इसकी अगुवाई करेंगे। फिलिस्तीन की मांग है, इज़्राइल तत्काल जंग रोके। उसकी तबाह-बरबाद बड़ी आबादी के लिए वैश्विक राहत-पुनर्वास कार्य चलाने दे और फिलिस्तीन राष्ट्र का स्थायी समाधान करे।

वहीं तेल अबीब का कहना है कि हमारा के आतंकी हमले रोकने की स्थायी गारंटी दें और उसके नागरिक-सैनिक बंधकों को बिना शर्त रिहा करे, गाजा-पट्टी को मुक्त क्षेत्र रहने दे। इन्हें मानने में हर्ज ही क्या है? इस आम ख्याल के विपरीत, अंतिम नतीजे मिलने में कई पेंच हैं। फिर भी जंग कुछ दिनों के लिए ही सही, रोकी जा सकती है और बंधकों की रिहाई एवं राहत-पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा सकते हैं। पर 'जंग चलती रहेगी और बंधक रिहा भी होंगे' कि इज़्राइली उम्मीद को परत हुआ फिलिस्तीन मानने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हमले के जवाब में जोरदार हमले हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की इस दबावकारी नीति का विरोध उनके अपने घर में हो रहा है। खास कर तीन बंधकों के शव मिलने के बाद बाकी को जिंदा छोड़ने के मुद्दे पर इज़्राइली सड़कों पर हैं। यह स्थिति इसके बावजूद है कि इज़्राइली हमले में 35 हजार से भी अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इसने पूरे विश्व को सिहरा दिया है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का नेतन्याहू को तत्काल जंग रोकने और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश इसी संदर्भ में है। वार्ता पर नई रजामंदी-जंग के बीच ही सही-नेतन्याहू पर बन रहे इसी दबाव को जाहिर करता है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां भी इसी तरफ बढ़ रही हैं। संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन के दोस्त हो जाने के बावजूद हाथ मिलाते-मिलाते रह गए सऊदी अरब के प्रिंस ने यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों के बीच साफ कर दिया है कि द्वि-राष्ट्रवाद ही समस्या का स्थायी समाधान है। भारत कब से इसी शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का पैरोकार रहा है।

आज का राशिफल



डॉ. बिपिन पाण्डेय ज्योतिष विभाग लखनऊ, वि

मेघ-आज मन खुश रहेगा व जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के आसार हैं आपको थोड़ा संयम से रहने की आवश्यकता होगी। आपके परिवार का कोई सदस्य आपके लिये मार्गदर्शक बनेगा। धकान महसूस होगी। आराम के लिए समय निकालें।

वृष-आज आपको स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य हासिल करने में थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है लेकिन उन्हें इस कड़ी मेहनत का अपेक्षित परिणाम भी हासिल होगा। दिन की शुरुआत में आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है।

मिथुन-आज अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता न करें, क्योंकि इससे आपकी बीमारी और बिगड़ सकती है। पैसे कमाने के नए मौके मुनाफा देंगे। आपको पहली नजर में किसी से प्यार हो सकता है। घर में मरम्मत का काम या सामाजिक मेल-मिलाप आपको व्यस्त रखेगा। व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है।

कर्क-दुश्मन की ताकत का अंजना लगाए बिना उलझना ठीक नहीं है। जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें। धर्म-कर्म में आस्था बढ़ेगी। विरोधी परास्त होंगे। महत्वपूर्ण कार्य में विलंब संभव है। लाभ होगा। अपने प्रेमी या जीवनसाथी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

सिंह-आज पुरानी गलतियों को लेकर भय बना रहेगा। साझेदारी में चल रहा गतिरोध दूर होने के आसार है। आयत-निर्यात के कारोबार में बड़ा लाभ संभव है। समान विचारधारा वाले लोगों के साथ काम करना आसान रहेगा। दूसरों की गलती अपने पर आ सकती है। काम में देरी से लाभ की मात्रा सीमित होगी।

कन्या-आज के दिन आपको सुख-समृद्धि, कार्यक्षेत्र में उन्नति, सुखद सफल यात्राएं, परिवार और जीवन साथी का सहयोग सब मिलने के आसार हैं। विवाहित व्यक्ति अपने जीवनसाथी में पूर्णतया विश्वास जतारें अन्यथा संबंधों में खटास पैदा हो सकती है। आपके कर्मक्षेत्र, आपके सम्मान व आपके नाम पर पड़ने के आसार हैं।

तुला-आज भाग्य आपके साथ है। लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंधों को नया रूप देने के लिए अच्छा मौका है। आज स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। आत्मिक सेहत बिगाड़ सकती है और कई जरूरी काम भी रूक सकते हैं। परिवार के लोग आपसे थोड़े नाराज हो सकते हैं।

वृश्चिक-आज आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं, इससे बचने के लिए कहीं बाहर जाएं और दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएं। आज जिस नए समारोह में आप शिरकत करेंगे, वहाँ से नयी दोस्ती की शुरुआत होगी। आज आपको प्रिय आपके साथ में समय बिताने और तोहफे की उम्मीद कर सकता है।

धनु-आज आपके परिश्रम से किए गए कार्य में सिद्धि होगी। नौकरी में आप का सम्मान बढ़ेगा। यात्रा के दौरान आप नयी जगहों को जानेंगे। और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। आप अपने प्रिय द्वारा कही गयी बातों के प्रति काफी संवेदनशील होंगे। अगर आप सुझ-बुझ से काम लें, तो आज अतिरिक्त धन कमा सकते हैं।

मकर-आज आपके आय के नए स्रोत बनेंगे। आकस्मिक धन के अवसर मिलेंगे। मित्रों और जीवनसंगिनी के सहयोग से राह आसान होगी। आध्यात्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। दपध्तर का तनाव आपकी सेहत खराब कर सकता है। अपने जज्बात पर काबू रखें। आज आपको अपने प्रिय की याद सताएगी।

कुंभ-आज आप कठिनाई से जुड़े फैसले खुद करें, बाद में इसका लाभ आपको मिलेगा। सहकर्मियों और कनिष्ठों के चलते चिंता और तनाव के क्षणों का सामना करना पड़ सकता है। माता-पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। आज दोस्तों के साथ बाहर घूमना आपके मन को खुशी देगा।

मीन-आज भाग्य पर निर्भर न रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें। आप उन लोगों की तरफ आपके का हाथ बढ़ाएंगे, जो आपसे मदद की गुहार करेंगे। यह दिन आपके सामान्य वैवाहिक जीवन से कुछ हटकर होने वाला है। यह दिन आपके सामान्य वैवाहिक जीवन से कुछ हटकर होने वाला है।

मंत्रिमंडल में अनुभवी व्यक्ति समाधान कर लेंगे

अवधेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 72 सदस्यीय मंत्रिमंडल के बारे में यह टिप्पणी उचित नहीं लगती कि इसके पीछे गठबंधन दलों के साथियों का बहुत ज्यादा दबाव है। 72 सदस्यीय मंत्रिमंडल में शीर्ष स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और यहां तक कि सड़क परिवहन, रेल तथा शिक्षा मंत्री भी पूर्व सरकार के ही हैं। विरोधी मोदी को तानाशाह या लोकतंत्र विरोधी की उपाधि देते रहे हैं। उनकी आलोचना अभी भी जारी है और वे कह रहे हैं कि मोदी गठबंधन सरकार नहीं चला पाएंगे क्योंकि उनका स्वभाव ही गैर लोकतांत्रिक है। इस तरह की विरोधी आलोचनाओं पर टिप्पणी करने की जगह हमें समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2001 से अभी तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में कभी बहुमतविहीन सरकार नहीं चलाई। वह जिस तरह बड़े कठोर निर्णय साहस के साथ करते रहे हैं उनका ध्यान करते हुए अनेक लोगों का मानना है कि यह स्वभाव गठबंधन सरकार चलाने के रास्ते की बाधा बन जाएगा। गठबंधन सरकार को लेकर लोग आशंकाएं उठाएंगे, लेकिन मोदी के अंदर सरकार चलाने तथा काम करने की इच्छा है।

वैसे मंत्रिमंडल गठन से लेकर विभागों के बंटवारे तक यह कहना कठिन है कि प्रधानमंत्री दबाव में काम कर रहे हैं। थोड़े शब्दों में कहें तो मोदी का 72 सदस्यीय मंत्रिमंडल भारत के भविष्य को लेकर उनकी योजनाओं, राजनीतिक आवश्यकताओं, साथी दलों के बीच संतुलन बनाने के साथ अनुभव, उम्र आदि के बीच समन्वय बनाने की कोशिश है। पिछली सरकार के 37 मंत्री इसमें हैं। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की स्वास्थ्य मंत्री के रूप में वापसी हुई है। सहयोगी दलों में हिंदुस्तान आवाग मोर्चा (हम) के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री 78 वर्षीय जीतन राम मांझी, जद (यू) के राजीव रंजन सिंह, तेलुगू देशम के 36 वर्षीय के राममोहन नायडू, लोजपा के 41 वर्षीय चिराग पासवान और 37 साल की रक्षा खड्गसे जैसी सरकार की सबसे युवा मंत्री को आधार बनाएं तो कैबिनेट का चेहरा आपकी समझ में आ जाएगा। पिछली सरकार में केवल तीन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के थे। इस बार इनकी संख्या 5 हो गई है। इनमें हरियाणा से रविंद्रजीत सिंह, जम्मू-कश्मीर से जितेंद्र सिंह और राजस्थान से अर्जुन राम मेघवाल की स्थिति पिछले सरकार के समान है। उत्तर प्रदेश से रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्यमंत्री बनाया गया है।



का प्रतिनिधित्व है। पंजाब से भाजपा का कोई सांसद नहीं है, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू को राज्य मंत्री बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश के परिणाम को देखते हुए माना जा रहा था कि वहां से कम मंत्री होंगे, लेकिन 10 मंत्री बनाए गए हैं और बिहार से आठ। सात महिलाएं हैं। केरल में भाजपा की पहली बार विजई हुई है इसलिए सुरेश गोपी को मंत्री पद मिलना ही था। दूसरे नेता केरल भाजपा के महासचिव जॉर्ज कोरियन हैं जिन्होंने 1970 में जनसंघ से लेकर लगातार भाजपा के लिए संघर्ष किया था। बंगाल से दो लोक सभा सदस्यों डॉ. सुकांत मजूमदार

बिहार सरकार को तगड़ा झटका

पटना हाई कोर्ट ने 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किए गए राज्य सरकार के आरक्षण को रद्द कर दिया है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार को तगड़ा झटका माना जा रहा है। यह दलितों, पिछड़े वर्गों व आदिवासियों को सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में दिया जा रहा था। बिहार की तत्कालीन महागठबंधन सरकार द्वारा बीते साल नवम्बर में जाति गणना के आधार पर इन वर्गों के लिए आरक्षण सीमा बढ़ाने का कानून बनाया गया था। अदालत ने विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के बाद इस बड़ी आरक्षण सीमा को संविधान के अनुच्छेद 14, 16 व 20 का उल्लंघन बताया। जैसा कि शीर्ष अदालत पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि कोई भी राज्य सरकार 50 प्रतिशत की तय सीमा से अधिक कोटा नहीं लागू कर सकती है, जबकि बिहार में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10 फीसद मिलाकर यह आरक्षण 75 प्रतिशत पहुंच गया था।

अदालत का मानना है कि बिहार में कुल जनसंख्या के केवल 1.57 प्रतिशत लोग ही सरकारी नौकरियों में हैं। जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व भी पर्याप्त बताया जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार इस

आदेश के खिलाफ सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। दरअसल, जैसा नजर आता है कि आरक्षण अब राजनीतिक पार्टियों के लिए जनता को फुसलाने का साधन माना रह गया है। उनका ध्येय समाज में व्याप्त गैर-बराबरी को मिटाना नहीं रहा। वे मतदाताओं को बड़ी तादाद में प्रभावित करने के उद्देश्य से व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते नजर आते हैं। तमाम अगड़ी जातियां मानती हैं कि आरक्षण के चलते नौकरियों क लाले पड़ रहे हैं। वे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के प्रभावित होने का रोना भी रोती रहती हैं, परंतु यह भी गलत नहीं है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न जातियों के समुदायों को जबरदस्त अन्याय सहना पड़ा है। उनके लिए कोटा तय कर, उन्हें सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक तौर पर बराबरी पर लाने के प्रयासों पर अड़चन लाने उचित नहीं है। यूं तो अन्य राज्यों में भी सत्ताधारी दल लाभ के लोभ में कोटा बढ़ाते रहने को उतावले हो सकते हैं। इसलिए बिना देरी किए, इस पर लगाम लगाना लाजमी है। कमजोर वर्ग की सहूलियत के लिए, उन्हें सहायता देने व जीवन स्तर बेहतर बनाने के अन्य तरीकों पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।

डूबती दिल्ली, मरते लोग, दोषी कौन ?

आर.के.सिन्हा राजधानी दिल्ली में इस बार मानसून के मौसम में हो रही भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश के पानी के कारण हो रहे जलभराव में लोग डूब रहे हैं या फिर उनकी पानी में खुली बिजली की तारों से करंट लगने के कारण जानें जा रही हैं। ये हादसे दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार की काहिली और नकारापन की चीख-चीख कर पुष्टि कर रहे हैं। यूं तो हरेक बारिश के मौसम में दिल्ली में जलभराव के कारण लगने वाले लंबे जाम के कारण लाखों लोगों की जिंदगी दूभर हो ही जाती है। पर इस बार बारिश के कारण यहां वहां जमा पानी में लोगों की डूबने के कारण अनेकों जानें भी जा रही हैं। साफ है कि जिन सरकारी एजेंसियों, अफसरों और कर्मियों पर देश की राजधानी को ठीक-ठाक रखने की जिम्मेदारी है, वह अपने दायित्वों को लेकर कतई गंभीर नहीं हैं। इन सरकारी महकमों में कसकर व्याप्त करप्शन भी इस कर्तव्यहीनता का मुख्य कारण है। कुछ दिन पहले देश की संसद भवन से पांचेक किलोमीटर दूर ओल्ड राजेन्द्र नगर में तीन नौजवान तब डूब कर मर गए थे, क्योंकि वे जिस बेसमेंट में बैठकर पढ़ रहे थे, वहां पानी भर गया था। दिल्ली की मेयर शैली आनंद के क्षेत्र से ओल्ड राजेन्द्र नगर की एक किलोमीटर भी नहीं है। इसके बावजूद वहां इतना बड़ा हादसा हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद ओल्ड राजेन्द्र नगर से दो मिनट की दूरी पर स्थित न्यू राजेन्द्र नगर में रहते हैं। पर उनकी पार्टी ने उनकी भी कोई क्लास नहीं ली। हादसे के लिए मात्र दो-तीन निगम के निम्न वर्गीय कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। सवाल यह है कि इस हादसे के लिए दिल्ली की मेयर ने अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? हाल ही में बेल मिलने के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी अपनी दिल्ली सरकार के कामकाज की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। पर वे यहां जलभराव के कारण हुई मौतों पर चुप हैं। एक उम्मीद पैदा हुई थी कि ओल्ड राजेन्द्र नगर की भयानक घटना के बाद यहां नगर निगम कायदे से काम करने लगेगा। उस घटना से दिल्ली खासी व्यथित थी। जनता में गुस्सा था। पर नगर निगम का चाल-चरित्र-चेहरा नहीं बदला।

राजधानी में लोगों की जाने जाती रहीं, क्योंकि तेजी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरना जारी रहा और सड़कों पर पैदल चलने वालों की जान पर बन आई। दो बच्चों की करंट लगने और डूबने से मौत हो गई। दिल्ली में इस मानसून में अब तक मरने वालों की अबतक ज्ञात कुल संख्या 33 हो गई है। इतने लोगों की मौत के बावजूद यहां पर सब कुछ सामान्य रफ्तार से चलना साबित करता है कि समाज अब पूरी तरह संवेदनहीन हो चुका है। वह कभी दृकभार ही अपनी तीखी प्रतिक्रिया देता है।

देखिए, जलवायु संकट मानसून में अप्रत्याशित पैटर्न पैदा कर रहा है, जिससे छोटे, लेकिन बहुत भारी बारिश के झोंके अब सामान्य से हो गए हैं। इसके लिए टोस योजना की आवश्यकता है, न कि बाद में किए जाने वाले उपायों की। पर हमारे यहां बंदले हुए हालात के अनुसार नहीं चला जाता है। सब काम चालू तरीके से होता है। जाहिर है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम झेलने पड़ते हैं। हम अपनी याददास्त को अगर टटोलें, तो पाएंगे

कि पर्यावरण में सुधी जनों ने चेतावनी इसलिए ही बहुत पहले ही दी थी। यकीन मानिए हमारे बहुत सारे सरकारी विभागों को लकवा मार गया है। वहां कोई आगे बढ़कर स्वेच्छा से काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। जाहिर है, इस मानसिकता के कारण ही बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। यह सब होने के बाद भी सरकारी अफसरों और दिल्ली सरकार के मंत्री किसी भी प्रकार



की जवाबदेही के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों नहीं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होता जिनकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं या दिल्ली पानी-पानी हो रही है।

अजीब सी स्थिति है कि एक तरफ दिल्ली बारिश के कारण डूब जाती है, दूसरी ओर दिल्ली वालों को पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं होता। राजधानी में पानी से जुड़े सारे मामलों को दिल्ली जल बोर्ड देखता है। दिल्ली जल बोर्ड का सर्वाधिक हाल बेहाल है। दिल्ली की आप सरकार के मंत्री और नेता रोज केन्द्र सरकार पर आरोपों की बौछार करने का कोई भी अवसर जाने नहीं देते। वे चिर असंतुष्ट प्राणी हैं। उन्हें सबसे शिकायतें हैं। वह कभी खुद भी अपने गिरेबान में झांक तो लें। वह खुद कब इस सवाल का जवाब देंगे कि वह दिल्ली को पेयजल के संकट से फलां-फलां तारीख तक उबार देंगे ? दिल्ली का मतलब सिर्फ हरे-भरे पेड़ों से लबरेज नई दिल्ली का लुटियन क्षेत्र ही नहीं है। राजधानी का मतलब दक्षिण

और मनुआ समुदाय के शांतनु ठाकुर को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। सुकांत उत्तरी बंगाल से हैं तो शांतनु ठाकुर दक्षिण बंगाल के मनुआ समुदाय से हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग में आते हैं। भाजपा ने उत्तर बंगाल की आठ में से 5 सीट पर जीत दर्ज की है। शांतनु ठाकुर कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले में बनागांव सीट से जीते तो सुकांत उत्तर बंगाल की बालूगघाट सीट से। बंगाल में यदि बेहतर विजय मिली होती तो वहां से और मंत्री बनाए जाते। इस तरह कोई नहीं कह सकता कि यह मंत्रिमंडल कुछ क्षेत्र, समूह, कुछ जातियां या परिवारों तक सीमित है।

इन सबको एक साथ मिलाकर देखें तो पहले निष्कर्ष आएगा कि यह नीतियों और व्यवहार में निरंतरता का मंत्रिमंडल है। सीसीएस यानी सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2019 से हैं। इसलिए नीति में कोई बदलाव होगा ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। निश्चित रूप से विश्व की दृष्टि मंत्रिमंडल पर रही होगी और संदेश जा चुका है कि रक्षा, सुरक्षा, विदेश, वित्त सहित अन्य प्रमुख मामलों में नीतियां और व्यवहार स्थिर रहने वाली हैं। एक पार्टी की बहुमत तथा गठबंधन की सरकार के कार्य व्यवहारों में अंतर रहा है। देश का आर्थिक विकास, सड़कों का विस्तार, अंतरिक्ष सुरक्षा तथा रक्षा के मामले में सक्षमता और आत्मनिर्भरता का विरोध कौन पार्टी करेगा? जिन्हें विवादास्पद कहा जा रहा है उनमें सर्वोपरि समान नागरिक संहिता है जो भाजपा के चुनावी वादों में शामिल है। इस संदर्भ में मोदी सरकार के कदमों को लेकर दृष्टि रखनी होगी। हालांकि जद (यू) ने इसका विरोध नहीं किया केवल ठीक प्रकार से विचार कर लाने की बात की थी। भाजपा को बहुमत होता तो समान नागरिक संहिता को संसद के पटल पर लाने और पारित करने में समस्या नहीं होती। क्या मोदी सरकार इस विषय को

कुछ समय के लिए एजेंडा से बाहर रखेगी? अगर गठबंधन से 72 में केवल 11 मंत्री हैं तो इसे दबाव में आना तो नहीं कह सकते। वैसे भी मंत्रिमंडल में इतने अनुभवी व्यक्ति हैं कि कोई मतभेद या सहमति उभरने पर अपने अनुभव के आधार पर वह समाधान कर लेंगे। इतने अनुभवी नेताओं के रहते हुए तत्काल यह नहीं मानना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी की अगले 5 वर्षों में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था तथा 2047 तक विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाने जैसे लक्ष्य के मार्ग में मंत्रिमंडल आपसी मतभेद के कारण बाधा बन जाएगा।



दिल्ली, उत्तर दिल्ली, पश्चिम दिल्ली या यमुना पार की सभ्रांत आवासीय कॉलोनियां भी नहीं है। दिल्ली के लाखों नागरिक उन अनधिकृत कॉलोनियों, घनी बस्तियों, झुग्गियों में भी जीवन यापन करने के लिए अभिशप्त हैं, जहां पर पीने का पानी मयस्सर नहीं है। जरा सोचिए कि किन हालातों में भीषण गर्मी के मौसम में लोग रहते होंगे। राजधानी के लाखों नागरिकों के घरों में पीने का पानी नहीं आता। यह अभाग्य हर रोज निजी जल आपूर्तिकर्ताओं अपने दिन भर के से उपयोग के लिये पानी खरीदते हैं। दस लाख की आबादी वाले संगम विहार में दिल्ली जल निगम से पानी की सप्लाई नहीं होती। यह हाल है दिल्ली का।

जल संकट से जूझ रहे दिल्ली में लगभग आधे जल निकायों का अतिक्रमण और अन्य कारणों की वजह से नष्ट हो जका प्रशासनिक विफलता का संकेत है। दुनिया के सबसे अधिक जल संकट वाले शहरों में से एक, दिल्ली ने आधिकारिक तौर पर सूचीबद्ध अपने लगभग आधे जल स्रोतों को खो दिया है। जिस समय देश आजाद हुआ था, उस समय दिल्ली के 362 गांवों में 1012 तालाब थे। यह सरकारी आंकड़ा है। एक सर्वे में पता चला है कि दिल्ली में दो हजार से अधिक तालाब और बावड़ियां होती थी। आबादी बढ़ने और दिल्ली के विकास के साथ अधिकतर तालाब खत्म कर दिए गए। कई तालाबों पर कॉलोनियां बस गईं। जो तालाब बचे हैं, उनमें से आधे से अधिक लगभग सूख चुके हैं। इन तालाबों को फिर से जीवित करना होगा। जानकार मानते हैं कि राजधानी में 500 से अधिक तालाब ऐसे हैं जिन्हें बारिश के पानी से पुनर्जीवित किया जा सकता है और बारिश की पानी से दिल्ली को जलमग्न होने से बचाया जा सकता है। बहुत साल पहले यमुना-तालाब पर जीवन खपा देने वाले अनुभव मिश्र ने सुझाया था कि यमुना का भी पुनर्जीवन संभव है। अगर यमुना के किनारे वजीराबाद से ओखला के बीच बड़े तालाबों की एक श्रृंखला बनाई जाये।

यदि दिल्ली में हमने जल का सही तरह से संरक्षण करना नहीं सीखा तो यहां पर पानी को लेकर भविष्य के दिनों में भारी खून-खराबा होगा। अभी भी बहुत सी अनधिकृत बस्तियों में पानी को लेकर सुबह रोज झगड़े होते हैं। कल तक हो चुके हैं। जल के स्रोत सीमित हैं। नये स्रोत हैं नहीं, ऐसे में जल स्रोतों को संरक्षित रखकर एवं जल को बचाकर ही हम जल संकट का सामना कर सकते हैं। इसके लिये हमें जल के उपयोग में मितव्ययी बनना पड़ेगा। जल प्रबंधन को बेहतर करना होगा। यदि वर्षाजल का समुचित संग्रह हो सके और जल के प्रत्येक बूंद को अनमोल मानकर उसका संरक्षण किया जाये तो जल संकट का समाधान संभव है। राजधानी में रोज लाखों कारों और दूसरे वाहनों की धुलाई पर बहुत पानी बर्बाद हो जाता है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता कि इस लिहाज से पानी की बर्बादी कैसे रोकी जाए। दिल्ली को अब जल संरक्षण के मसले पर सेंसिटिव होना होगा। अबपानी के इस्तेमाल में हमें मितव्ययी बनना होगा। छोटे-छोटे उपाय कर जल की बड़ी बचत की जा सकती है। मसलन हम दैनिक जीवन में पानी की बर्बादी कतई न करें। समाज को खुद ही और अपने मसले हल करने होंगे। यहां की दिल्ली सरकार से अब कोई उम्मीद करना बेकार है।

